राइजिंग राजस्थान के लिए उर्जा विभाग के प्री-समिट सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में 6.57 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान को विश्व की अक्षय ऊर्जा का केन्द्र बनाने का आव्हान किया

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, एक्सिस एनर्जी वैंचर्स, एस.जे.वी.एन. ग्रीन एनर्जी जैसी प्रमुख कंपनियों ने एम.ओ.यू. किया

जयपुर, 20 नवंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आज एनर्जी प्री-समिट में ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के साथ 6.57 लाख करोड़ रुपये के निवेश एम.ओ.यू. का आदान-प्रदान किया गया। आज हस्ताक्षिरत एम.ओ.यू. में सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन, हाइब्रिड, पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज और हरित अमोनिया परियोजनाओं सहित, अक्षय ऊर्जा और बिजली उत्पादन क्षेत्र के विभिन्न खंडों में परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हस्ताक्षिरत निवेश प्रस्तावों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन से राज्य में लगभग 70000 नए रोजगार सृजित होंगे।

राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निवेशकों से आ ान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करता है। राज्य में 2245 मेगावाट की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है, यहाँ 325 दिन से अधिक धूप रहती है, हमारे पास सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में असीमित अवसर मौजूद हैं। हमारा लक्ष्य राजस्थान को एक एनर्जी-सरप्लस राज्य बनाना है, जो न केवल प्रदेश, बल्कि अन्य राज्यों और देशों की मांगों को भी पूरा करने में भी सक्षम हो।"

> ■ आज के प्री-समिट में 6.57 लाख करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए, जिनसे 70 हजार नये रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। कुल 28 निवेशकों ने सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन, हाईब्रिड, पंप भण्डारण, बैटरी भण्डारण, हरित अमोनिया परियोजना के लिए एम.ओ.यू. किये।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 लाएगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में कई नए संभावनाओं, जैसे कि पंप भंडारण, हरित हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण, जैव ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद राजस्थान सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा, "सरकार निवेशकों की व्यापक निगरानी और मार्गदर्शन के माध्यम से एम.ओ.यू. के शीघ्र क्रियान्वयन की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समिट से पहले अक्षय ऊर्जा के विविध क्षेत्रों में एम.ओ.यू. होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत भारी मात्रा में निवेश जुटाने में सबसे आगे रहा है।

इस अवसर पर राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य, सचिव-ऊर्जा श्रीआलोक ने कहा, "राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र और सही नीतिगत माहौल बनाया है, जो न केवल राजस्थान के ऊर्जा परिवर्तन में, बल्कि पूरे देश के लिए योगदान देगा।"

इस अवसर पर उपस्थित अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में आर.आर.ई.सी. के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आलोक गुप्ता, डिस्कॉम्स की अध्यक्ष आरती डोगरा, राजस्थान सरकार के आर.वी.पी.एन.एल. के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल, आर.आर.ई.सी.एल. और आर.यू.वी.आई.टी. के प्रबंध निदेशक ओम प्रकाश कसेरा और राजस्थान सरकार के अन्य अधिकारी शामिल थे।

करहल सीट पर कम मतदान से सपा चिंतित

मैनपुरी 20 नवंबर। समाजवादी पार्टी (सपा) के गढ़, मैनपुरी की करहल विधानसभा में बुधवार को संपन्न उपचुनाव में कम मतदान का खामियाजा सपा को मिलने के आसार जताये जा रहे हैं। यहां मतदान का प्रतिशत 53.89 रहा।

मतदान के दौरान कहीं से कोई बड़ी घटना प्रकाश में नहीं आयी। मतदान केंद्र शाहजहांपुर में ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान एक घण्टे तक बाधित रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया।

> ■ यहाँ के यादव बाहुल्य क्षेत्रों में भाजपा के बस्ते नहीं लगते थे, वहाँ इस बार भाजपा के एजेन्ट नज़र आये।

मतदान के बाद सपा और भाजपा के नेता अपनी-अपनी जीत के दावे नजर करते आये। करहल के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव की तैयारियां मतदान के दिन दिखाई दीं। यादव बाहुल्य गांवों में पूर्व के चुनावों में भाजपा के बस्ते नहीं लगते थे। वहां भाजपा के एजेंट भी नजर आए और बस्ते भी लगे।

अनुजेश यादव ने कहा कि लोगों का उन्हें मतदान के दिन भारी समर्थन मिला है और करहल में इस बार भाजपा जीतेगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मलिंगा ने सरेंडर किया

एस.सी.-एस.सी. कोर्ट से पुलिस मलिंगा को कोतवाली तक आधा किलोमीटर पैदल ले गई

धौलपुर / रूपवास, 20 नवम्बर (निस)। पूर्व विधायक व भाजपा नेता गिर्राज सिंह मलिंगा ने बुधवार शाम 4:15 बजे धौलपुर के एस.सी.-एस.टी. कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने मलिंगा को 2 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है।

कोर्ट में सरेंडर के बाद, पुलिस बाड़ी के पूर्व विधायक मलिंगा को आधा किलोमीटर तक पैदल ही लेकर कोतवाली थाने पहुंची। इसके बाद, कोतवाली थाने के सामने से मलिंगा को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर धौलपुर जेल तक ले जाया गया। करीब ढाई साल पुराने ए.ई.एन.-जे.ई.एन. मारपीट मामले में 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मलिंगा को 14 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और अरविंद कुमार की बेंच ने 8 नवंबर को मलिंगा की जमानत पर हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हटा दी थी। विधायक द्वारा सरेंडर करने के 4 सप्ताह बाद मामले में सुनवाई होगी।

ज्ञातव्य है कि धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में 28 मार्च 2022 को हर्षदापति और नितिन गुलाटी के साथ मारपीट की घटना हुई थी। प्रकरण में ए.ई.एन. हर्षदापति ने मलिंगा (तत्कालीन कांग्रेस विधायक) और अन्य के खिलाफ 29 मार्च को मारपीट, राजकार्य में बाधा और एस.सी.-एस.टी. एक्ट में नामजद केस दर्ज कराया था। केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद, तत्कालीन धौलपुर एस.पी. शिवराज मीणा का भी तबादला कर दिया गया था। बिजली विभाग के इंजीनियर्स के साथ मारपीट होने के बाद, निगम के कर्मचारियों में आक्रोश भड़क गया था। उसके बाद गिर्राज मलिंगा ने 11 मई को जयपुर के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के सामने सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 17 मई को जमानत दी थी।

> ■ ढाई साल पुराने ए.ई.एन.-जे.ई.एन. मारपीट मामले में 8 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने मलिंगा को 14 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिये थे।

गिर्राज सिंह मलिंगा ने पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर बाड़ी सीट से लड़ा था और बसपा के जसवंत सिंह गुर्जर से चुनाव हार गए थे। इससे पहले, मलिंगा लगातार 15 साल तक इस सीट से विधायक रहे थे। पहली बार वे 2008 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस जॉइन कर ली। कांग्रेस के टिकट पर वे 2013 और 2018 में विधायक बने। लेकिन, जब कांग्रेस ने उन्हें पिछले चुनाव में टिकट नहीं दिया तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा जॉइन कर ली थी।

ज्ञातव्य है कि हर्षदापति कांग्रेस नेता कैप्टन मुकेश वाल्मीकि का बेटा है। मुकेश वाल्मीकि साल 2003 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इस मामले में तत्कालीन डी.जी.पी. एम.एल. लाठर ने बाड़ी डी.एस.पी. बाबूलाल मीणा और कोतवाल विजय कुमार मीणा को सस्पेंड कर दिया था।

ऑर्गन ट्रांसप्लांट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। वहीं, हाईकोर्ट ने भी सह आरोपियों को जमानत देते हुए फर्जी एन.ओ.सी. जारी करने में उनकी कोई भूमिका नहीं मानी है। याचिकाकर्ता ने अस्पताल प्रशासन को एन.ओ.सी. मिलने के बाद ही ऑपरेशन किए थे। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने संगठित रैकेट में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो वह जांच का बाधित कर सकता है। ऐसे में उसकी एस.एल.पी. को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने एस.एल.पी. को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि अदालत ने गत 2 अक्टूबर को डॉ. ज्योति बंसल को अंतरिम राहत देते हुए उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में दिखी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विपक्ष सत्ता में आया तो वह इन सारी कल्याणकारी योजनाओं को बन्द कर देगा।

हाँ, अगर पूरे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर देखा जाये तो राज्य के सभी छः क्षेत्रों में आम आदमी की दुर्दशा साफ दिखाई देती है। और इन मुद्दों को उठाये जाने पर, सत्तारूढ़ महायुति सरकार के पार्टनर साफ तौर पर बैकफुट पर आ जाते हैं क्योंकि वे आम जनता की दुर्दशा के बिन्दु पर महा विकास अघाड़ी के हमलों का जवाब नहीं दे पाते। इसके अलावा, उद्धव ठाकरे की सरकार को "योजनाबद्ध तरीके से गिराने" के कारण, उनके प्रति पैदा हुई सहानुभूति के कारण, उन्हें जन समर्थन मिलना स्वाभाविक है। यह बात निश्चय- पूर्वक कही जा सकती है कि लोगों के मन में उस एम.वी.ए. सरकार के प्रति सहानुभूति है, जिसे ढ़ाई साल के अन्दर गिरा दिया गया था।

महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े हिस्सों में कुछ कल्याणकारी योजनाएं तो सत्तारूढ़ गठबन्धन के खिलाफ जा रही थीं, क्योंकि इन क्षेत्रों की महिलाओं को मालूम है कि कृषि, कृषक तथा उनके परिवार किस दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं।

यहाँ, सब्सिडी और एम.एस.पी. बहुत बड़े मुद्दे हैं, तथा यही कारण है कि चुनाव-प्रचार के अन्तिम दिनों में, केन्द्र सरकार सोयाबीन के संशोधित एम.एस.पी. पर विचार करने लगी तथा कृषि मन्त्रालय ने इस फसल की 7000 रू. की नई दर का मानस बना लिया था। महाराष्ट्र में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है, इसलिये यह बहुत बड़ा मुद्दा है तथा यह मुद्दा सत्तरूढ़ गठबन्धन की आशाओं पर पानी फेर सकता है। दूसरी तरफ, विपक्ष अपने चुनावी वादों के अन्तर्गत, सोयाबीन सहित, अन्य बहुत से कृषि उत्पादों की एम.एस.पी. बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर चुका है।

यह मान लेना गलत होगा कि विधान सभा चुनावों में इस प्रकार के मुद्दे बहत प्रभावी हैं, क्योंकि इन चुनावों की प्रकृति ही ऐसी है कि इनमें स्थानीय तथा अतिस्थानीय मुद्दे इस हद तक प्रभावी रहते हैं कि ये चुनाव एक प्रकार से पंचायत चुनावों से मेल खाने लगते हैं।

एग्ज़िट पोल्स ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विजय की भविष्यवाणी की गई है।

झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। भाजपा ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा। ऑल झारखंड स्टूडैन्ट्स यूनियन (ए.जे.एस.यू.) ने 10 तथा जनता दल (युनाइटेड) ने 2 और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास पासवान) ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा है।

मात्रीस एग्ज़िट पोल द्वारा नैशनल डैमोक्रैटिक अलायंस (एन.डी.ए.) की 42-47 सीटों पर विजय की भविष्यवाणी की जा रही है, जबकि महागठबंधन को कुल 81 सीटों वाली विधानसभा में 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं।

पीपल्स पल्स के एग्ज़िट पोल ने एन.डी.ए. की, 44 से 53 सीटों पर विजय और इण्डिया ब्लॉक को 25 से 37 सीटें मिलने की बात कही है।

टाइम्स नाओ - जे.वी.सी. के अनुसार, एन.डी.ए. को 40-44 तथा महागठबंधन 30-40 सीटें मिल सकती हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सत्तारुढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने 30 तथा राष्ट्रीय जनता दल ने 6 सीटों पर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्कसिस्ट- लेनिनिस्ट) ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा।

झारखंड में मुख्य मुकाबला महागठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले एन.डी.ए. के बीच था।

पराली जलाने पर इटावा में डेढ़ लाख का जुर्माना

प्रशासन की चेतावनियों के बाद भी सौ से अधिक पराली जलाने के मामले सामने आये हैं

इटावा , 20 नवंबर। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जिला प्रशासन और कृषि विभाग की लाख चेतावनियों के बावजूद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब तक इटावा में एक सैकड़ा से अधिक पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। पराली जलाने वाले किसानों से करीब डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। किसानों द्वारा जलाई जा रही परली के कारण इटावा का मौसम व्यापक पैमाने पर प्रदूषित हो चुका है। जिला प्रशासन ने पराली जलाने पर रोक के लिए किसानों को बड़ी संख्या में जागरूक किया है । इस जागरूकता के बाद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं । पराली जलाने को लेकर कृषि विभाग ने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है । पराली जलाने की 100 से अधिक घटनाएं हुई है जिस पर विभाग ने संज्ञान लेते हुए जुर्माना करते हुए 157500 रुपए रकम वसूल की है।

> ■ कृषि विभाग ने सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने की घटनायें रिकार्ड कर भरथना तहसील में 25, इटावा सदर में 22 तथा सैफई में 13 किसानों से जुर्माना वसूला है।

कृषि विभाग ने सेटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं में सर्वाधिक भरथना तहसील में 25 किसानों, इटावा सदर में 22 किसान और सैफई में 13 किसानों से जुर्माना वसूल किया गया है।

कृषि विभाग के उपनिदेशक आर.एन.सिंह ने बताया कि जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है। दो एकड़ तक की भूमि वाले किसानों से पांच हजार रुपए, दो से पांच एकड़ पर दस हजार रुपए और 5 एकड़ से अधिक भूमि के किसानों से तीस हजार रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जा रहा है। लगातार पूरे जनपद में किसानों को पराली जलाने से रोका जा रहा है और उन्हें इससे होने वाले नुकसान के बारे में समझाया जा रहा है।

रविवार को संसद में सर्वदलीय बैठक

नयी दिल्ली, 20 नवंबर। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्रालय की बुधवार को एक विज्ञिप्त में यह जानकारी दी गयी। सर्वदलीय बैठक रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे संसद परिसर में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

> ■ संविधान दिवस पर 26 नवम्बर को दोनों सदनों की केन्द्रीय कक्ष में विशेष बैठक होगी।

संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो सकता है। 'संविधान दिवस' के उपलक्ष में 26 नवंबर को लोक सभा और राज्य सभा की कोई बैठक नहीं होगी। संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में 26 नवंबर को दोनों सदनों की एक विशेष बैठक होगी।

सपा प्रत्याशी ने मुरादाबाद जिले का उपचुनाव रद्द करने की मांग की

मुरादाबाद, 20 नवंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान ने मतदान में धांधली का आरोप लगाते हुये चुनाव आयोग से मतदान रद्द करने और पुर्नमतदान की मांग की है।

जिला प्रशासन ने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लघंन करने के आरोप में तीन पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटा दिया है और उनके ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिये हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने मंगलवार को बताया कि शिकायत मिलने पर लापरवाही बरतने के आरोप में एक दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटा दिया गया। जांचोपरांत उनके ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायती पत्र भेजा है। शिकायती पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी तंत्र और शक्ति का दुरुपयोग किया गया है। जिसमें एक वर्ग विशेष को मतदान करने दिया गया जबकि अन्य वर्ग के मतदाताओं की आईडी चैक करने की आड़ में बूथ तक पहूंचने से रोका गया।

> ■ सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान ने मतदान में धांधली का आरोप लगा, पुर्नमतदान की मांग की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने पर तीन पुलिस कर्मियों को ड्यूटी से हटाया।

क्या राष्ट्रपति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अली अहमद तथा नीलम संजीवा रेड्डी इस मानसिक द्विविधा से बच गये क्योंकि अनके कार्यकालों में, उनके पास कोई दया याचिका नहीं आई।

दूसरी तरफ, राष्ट्रपति कोविंद ने उन्हें प्राप्त सभी 6 दया याचिकाएं खारिज कर दी थी, इनमें जगत राय की दया याचिका भी शामिल थी, जो बिहार के वैशाली जिले के एक परिवार के छः सदस्यों की हत्या का अपराधी था।

राष्ट्रपति मुर्मू ने, उन्हें अब तक प्राप्त दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इनमें आतंकी आरिफ की दया- याचिका भी शामिल है, जो लाल किला हमले में लिप्त था।

चिकित्सक का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने मार्च, 2013 में फॉरेन मेडिकल परीक्षा भी पास की थी। वहीं, बाद में उसने एम.सी.आई. और आर.एम.सी. से अपना पंजीकरण कराया था। याचिका में बताया गया कि आर.पी.एस.सी. की ओर से चयनित होने के बाद वह कई सालों से चिकित्सक के रूप में काम कर रहा है। याचिका में कहा गया कि गत 6 नवंबर को राजस्थान मेडिकल काउन्सिल ने उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। इस दौरान न तो उसे नोटिस दिया गया और न ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया। ऐसे में आर.एम.सी. के आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

सूखे की स्थिति बन रही है हिमाचल प्रदेश में

राज्य में अक्टूबर माह में 97 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड हुई

शिमला, 20 नवंबर। हिमाचल प्रदेश में डेढ़ माह से सूखे की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में मानसून दो अक्टूबर को समाप्त हो गया। उसके बाद पूरे प्रदेश से बारिश नदारद रही है। हिमाचल प्रदेश में 2016 के बाद ऐसी स्थिति बनी है, जब नवंबर माह में भी बारिश नही हुई है। अक्टूबर माह में 97 फीसदी बारिश कम दर्ज की गई है। वहीं नवंबर माह में पूरी तरह सूखे की स्थिति बनी हुई है, और आने वाले दिनों में भी बारिश के आसार नही दिख रहे हैं।

22 नवंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में प्रवेश करेगा लेकिन मुख्यत: उसका असर प्रदेश में कम ही देखने को मिलेगा। वहीं, मैदानी क्षेत्रों में अभी कोहरे से निजात मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने कोहरे के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी।

> ■ मौसम विभाग के अनुसार 2016 में भी प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी थी। नवम्बर माह में दो पश्चिमी विक्षोभ आये, पर इनमें बहुत कम वर्षा हुई।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि नवंबर माह में दो पश्चिमी विक्षोभ 11 और 14 नवंबर को प्रदेश में आए। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई, लेकिन पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति अभी तक बनी हुई है। आने वाले तीन दिनों तक भी ऐसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है।

22 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में प्रवेश कर रहा है, परंतु इसका असर प्रदेश में कम देखने को मिलेगा। लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश व हल्की बर्फबारी हो सकती है। इसका असर बाकी प्रदेश में देखने को नही मिलेगा। तापमान में आने वाले दिनों में गिरावट दर्ज की जाएगी।

2016 में भी इसी तरह पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे प्रदेश में नहीं पड़ा था। इस वर्ष भी ऐसी स्थिति प्रदेश में बनी हुई है। आने वाला पश्चिमी विक्षोभ का मुख्यत: प्रभाव जम्मू-कश्मीर में होगा। हिमाचल प्रदेश से यह होकर जब गुजरेगा, उस समय कुछ असर इसका ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है।

तेलंगाना में जाति जनगणना का काम 70 फीसदी पूराः राहुल

नयी दिल्ली, 20 नवंबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना को जरूरी बताते हुए बुधवार को कहा कि तेलंगाना सरकार ने जाति जनगणना का 70 फ़ीसदी काम पूरा कर लिया है और जल्द ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा।

गांधी ने कहा, "तेलंगाना में हमारी सरकार ने जातिगत गिनती का 70 प्रतिशत से ज़्यादा काम पूरा कर लिया है। जल्द ही पूरे राज्य का विस्तृत डेटा सरकार के पास होगा, जिसका इस्तेमाल हम नीतियां बनाने और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए करेंगे।"

उन्होंने कहा,"जाति जनगणना उन सभी महत्वपूर्ण कदमों में से पहला कदम है जो अगले कुछ दशकों में संपूर्ण विकास के लिए योजना बनाने में मदद करेगा। यही कारण है कि मैं बार-बार देश में एक व्यापक जातिगत जनगणना करवाने की मांग कर रहा हूं। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने रास्ता दिखाया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम एक व्यापक जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे।"

मणिपुर की "इनर लाइन परमिट"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार को यह समय दिया।

शीर्ष अदालत ने "आमरा बंगाली" नामक एक संगठन द्वारा दायर की गई एक याचिका पर 3 जनवरी, 2022 को केन्द्र, मणिपुर सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी किये थे।

याचिका में कहा गया है कि आई.एल.पी. राज्य को ऐसा बेलगाम अधिकार देती है, जिसके तहत गैर-स्थानीय लोगों या उन लोगों, जो मणिपुर के स्थाई निवासी नहीं है, का आवागमन प्रतिबन्धित होता है। याचिका कहती है, "यह कठोर आई.एल.पी. व्यवस्था, राज्य के अन्दर पर्यटन, जो राजस्व सृजन का एक बड़ा स्रोत है, के अलावा इनर लाइन से परे के क्षेत्र में सामाजिक एकता, विकास एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित तरक्की की नीतियों के मूलरूप रूप से विरोध में है। इस याचिका में "मणिपुर इनर लाइन परमिट गाइडलाइन्स, 2019" को भी चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गय है कि 2019 का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 तथा 21 में नागरिकों को दिये गये गारन्टी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह आदेश राज्य में गैर-स्थानीय लोगों के आने एवं जाने को प्रतिबन्धित करने के अबाधित अधिकार राज्य को प्रदान करता है।

बार एसोसिएशन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनाव संचालन समिति का सदस्य बनाया गया है। चुनाव समिति की ओर से तय किया गया कि 12 नवंबर से 20 नवंबर तक अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर अपना शपथ पत्र पेश करेंगे। इसकी पालना में कुल 5804 वकीलों की ओर से वन बार वन वोट को लेकर अपने शपथ पत्र दिए गए हैं। समिति के सदस्य राजीव शर्मा ने बताया कि एक वकील कई बार एसोसिएशंस में सदस्य रहता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं कि एक वकील किसी भी एक बार एसोसिएशन में ही अपना वोट दे सकता है। इसलिए उनसे इस संबंध में शपथ पत्र लिए जाते हैं। इन शपथ पत्रों के परीक्षण के बाद 26 नवंबर को मतदाता सूची जारी की जाएगी। समिति के सदस्य राजेश कर्नल ने बताया कि नामांकन पत्र भरने की शुरुआत 29 नवंबर से आरंभ होगी, जो 5 दिसंबर तक चलेगी। वहीं, नामांकन पत्र वापसी के लिए 6 दिसंबर का दिन तय किया गया है। इसके साथ मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों को सात दिसंबर को बैलेट नंबर दिए जाएगे। वहीं, 13 दिसंबर को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा और उसके अगले दिन सुबह दस बजे से मतों की गणना कर परिणाम जारी किया जाएगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908